RNI No: **UPHIN/2023/86769**

www.swarajindianews.com

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

मूल्य: ₹ 02

कानपुर ,मंगलवार , 03 जून, 2025
वर्ष: 02, अंक: 155, पृष्ठ: 8+4

हरिद्वार नगर निगम जमीन घोटाला में बड़ी कार्रवाई -पुष्कर सिंह धामी

» Pg10

इनसाइड

245 पट्टों की मूल पत्रावली बिल्हौर तहसील से गायब! » Pg03

सपा को मात देने के लिए यूपी में बन रहा थर्ड फ्रंट !

बीजेपी छोटे-छोटे दलों को मिलाकर सत्ता की हैट्रिक लगाकर इतिहास रचना चाहती है

» आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद एनडीए और इंडिया गठबंधन से अलग सियासी गणित बना रहे हैं

मुख्य संवाददाता स्वराज इंडिया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में दो साल के बाद 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी बिसात अभी से ही बिछाई जाने लगी है. बीजेपी छोटे-छोटे दलों को मिलाकर सत्ता की हैट्रिक लगाकर इतिहास रचना चाहती है तो सपा ने कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी वापसी करने के जुगत में है. ऐसे में आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद एनडीए और इंडिया गठबंधन से अलग 2027 के लिए अपना सियासी ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है.

सपा के तर्ज पर आजाद समाज पार्टी ने दलित, पिछड़ा और मुस्लिम फार्मूले को अमलीजामा पहनाने के साथ-साथ एक अलग गठबंधन बनाने का प्लान बनाया है. सोमवार को लखनऊ में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर चंद्रशेखर आजाद ने नया गठजोड़ बनाने के संकेत दे दिए हैं. इस तरह से थर्ड फंट बनाने की दिशा में अपने कदम बढ़ाते नजर रहे हैं.

क्या चंद्रशेखर का थर्ड फंट कामयाब होगा?

नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद इस बात को बखूबी जानते हैं कि इंडिया गठबंधन में उनकी एंट्री होने वाली नहीं है और बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन के साथ जाकर जाना जोखिम भरा कदम होगा. मायावती पहले ही उन पर निशाना साधकर बता चुकी हैं कि बसपा के साथ दोस्ती किसी भी सूरत में संभव नहीं है. मायावती ने चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मोर्टा का लिए बगैर कहा था कि बसपा को कमजोर करने के लिए छोटे छोटे दल बनवाए जा रहे हैं. बसपा के खिलाफ छोटे राजनीतिक दल और संगठन बना रहे हैं. सत्ता और विपक्ष में रहने वाली पार्टियां बसपा के खिलाफ एकजुट हो रही हैं और बसपा को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं.

चंद्रशेखर-स्वामी प्रसाद ने मिलाया हाथ

चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच हुई मुलाकात को डा. भीमराव अम्बेडकर और कांशीराम के मिशन को आगे बढ़ाने वाले दो नेताओं की मुलाकात बताई जा रही है. यह मुलाकात अपनी जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय लखनऊ में हुई

और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सामाजिक न्याय, बहुजन एकता और आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई है. माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच एकजुटता और 2027 में मिलकर चुनाव लड़ने की स्ट्रैटेजी पर बात हुई है. इस तरह साफ है कि 2027 के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य आपसी गठबंधन कर किस्मत आजमा सकते हैं.

स्वामी प्रसाद मौर्य हार्डकोर आंबेडकरवादी नेता माने जाते हैं. लोकदल से लेकर बसपा, बीजेपी और सपा में रह चुके हैं. सपा के महासचिव व एमएलसी के पद से इस्तीफा देकर अपनी पार्टी का गठन किया. 2024 के लोकसभा चुनाव में कुशीनगर सीट से किस्मत आजमाया था, लेकिन जीत नहीं सके. अब 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश बढ़ने के साथ ही चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात नए गठबंधन बनने के संकेत दे रहे हैं.

यूपी पुलिस-पीएसी भर्ती में अग्निवीरों को भी मिलेगा कोटा!

» योगी आदित्यनाथ सरकार अग्निवीरों के लिए पुलिस और पीएसी भर्ती में 10 से 20प्रतिशत आरक्षण देने की तैयारी में है

» अग्निवीरों को आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी, जिससे 2027 में सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों को रोजगार मिलने में आसानी हो

मुख्य संवाददाता स्वराज इंडिया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। उन्हें पुलिस और पीएसी की भर्ती में आरक्षण मिलेगा। यह आरक्षण 10 से 20त्न तक हो सकता है। संभावना है कि मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हो रही कैबिनेट बैठक में गृह विभाग का यह प्रस्ताव रखा जाएगा।

गृह विभाग की तैयारी है कि 2023 में सेना में भर्ती हुए अग्निवीर जब 2027 में रिटायर होकर बाहर आएं तो उन्हें रोजगार की समस्या ना हो। इसी को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव में पुलिस और पीएसी की भर्ती में 10 से 20त्न आरक्षण की बात कही गई है। इसके साथ ही आयु सीमा में भी छूट देने की बात है ।गृह विभाग के अधिकारियों के अनुसार अग्निवीरों को दो श्रेणियों में बांटकर लाभ देने की योजना है। पहले श्रेणी में वे अग्निवीर होंगे, जो चार साल की सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इन्हें 15त्न आरक्षण और आयु सीमा में अधिकतम 3 साल की छूट मिलेगी ।दूसरी श्रेणी में वे अग्निवीर होंगे, जिन्हें चार साल की सेवा के बाद स्थायी नियुक्ति मिल जाएगी, लेकिन वे बीच में ही सेवा छोड़कर पुलिस सेवा में आना चाहेंगे। ऐसे अग्निवीरों को 10त्न आरक्षण और अधिकतम 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी ।कैबिनेट की बैठक में कई और विभागों के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।इन्हें एजेंडा में शामिल किया गया है। इनमें गृह विभाग से जुड़े प्रस्तावों की संख्या सबसे ज्यादा बताई जा रही है।

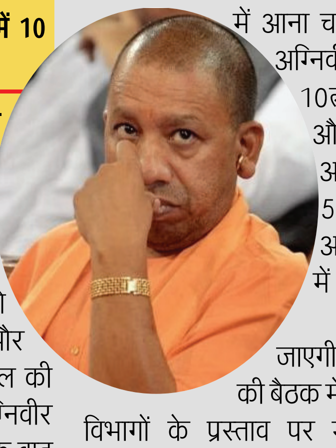

होम स्टे पॉलिसी में हो सकता है बदलाव

कैबिनेट की बैठक में होम स्टे नीति में बदलाव का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। राज्य सरकार की 2018 में बनी नीति में कई खामियां रह गई थीं, जिनके कारण इसका लाभ उठाने वाले लोगों को दिक्कत आ रही थी।

अब इस नीति में बदलाव करते हुए इसे आसान बनाया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, पर्यटन विभाग और नगर विकास विभाग इस नई नीति को अंतिम रूप दे चुके हैं।

कानपुर मेट्रो:समाजवादी नेताओं ने अखिलेश यादव की दूरदर्शिता के लिए जताया आभार

» विधायक अमिताभ बाजपेई ने कहा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया था कानपुर मेट्रो का शिलान्यास

स्वराज इंडिया संवाददाता

कानपुर। कानपुर मेट्रो परियोजना को लेकर शहरवासियों के बीच उत्साह का माहौल है। इसी क्रम में आज आर्यनगर विधायक श्री अमिताभ बाजपेई एवं छावनी विधायक श्री मोहम्मद हसन रूमी ने मेट्रो ट्रेन में सफर कर नवीन मार्केट से रावतपुर व घंटाघाट स्टेशन तक के रूट का जायजा लिया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं आम नागरिकों ने मेट्रो यात्रा का आनंद उठाया।

नेताओं ने मेट्रो सफर के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का विशेष रूप से आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि कानपुर मेट्रो परियोजना की आधारशिला अखिलेश सरकार के कार्यकाल में रखी गई थी। अगर आगामी सरकार समाजवादी पार्टी की बनती है तो मेट्रो परियोजना के जो भी कार्य अधूरे रह गए हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाएगा।

छावनी विधायक मोहम्मद हसन रूमी ने वर्तमान भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि मेट्रो का संचालन अधूरी तैयारियों के साथ शुरू कर दिया गया है। उन्होंने यात्रियों की सुविधाओं का हवाला देते हुए बताया कि स्टेशन परिसर में पीने के पानी, शौचालय एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की कमी से खासकर बुजुर्गों और महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। आम जनता की ओर से भी मेट्रो को लेकर सकारात्मक रुझान देखा गया। बड़ी संख्या में लोग अपने परिवारों के साथ मेट्रो सफर का लुत्फ उठा रहे हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला: बिकरु कांड के आरोपी जयकांत वाजपेयी की दूसरी जमानत याचिका मंजूर

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

इलाहाबाद/कानपुर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुचर्चित बिकरु कांड के आरोपी जयकांत वाजपेयी की दूसरी जमानत याचिका सशर्त स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश और मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए वर्तमान जमानत याचिका स्वीकार कर ली।

उक्त आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की एकलपीठ ने जयकांत वाजपेयी उर्फ जय की याचिका को स्वीकार करते हुए पारित किया।

कोर्ट ने जेल में क्षमता से 5-6 गुना अधिक विचाराधीन कैदियों की भीड़ पर विचार करने के उपरांत वर्तमान मामले को जमानत के योग्य पाया। मालूम हो कि याची के खिलाफ आईपीसी, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धारा 7 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं के तहत पुलिस स्टेशन चौबेपुर, जिला कानपुर नगर में मामला दर्ज कराया गया था। पिछले 5 वर्षों से याची जेल में बंद है।

याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 102 गवाह हैं, जिनमें से केवल 13 की अब तक जांच की गई है। सह-अभियुक्त उमाशंकर यादव उर्फ टांके को जमानत मिल चुकी है, साथ ही अन्य कई सह-अभियुक्तों की भी दूसरी जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई है। ऐसे में याची भी जमानत का हकदार है। बता दें कि कानपुर के चर्चित बिकरु कांड में मुख्य आरोपी विकास दूबे के खिलाफ कार्यवाही करते समय 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी, जिसमें 60-70 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और 21 को नामजद किया गया था।

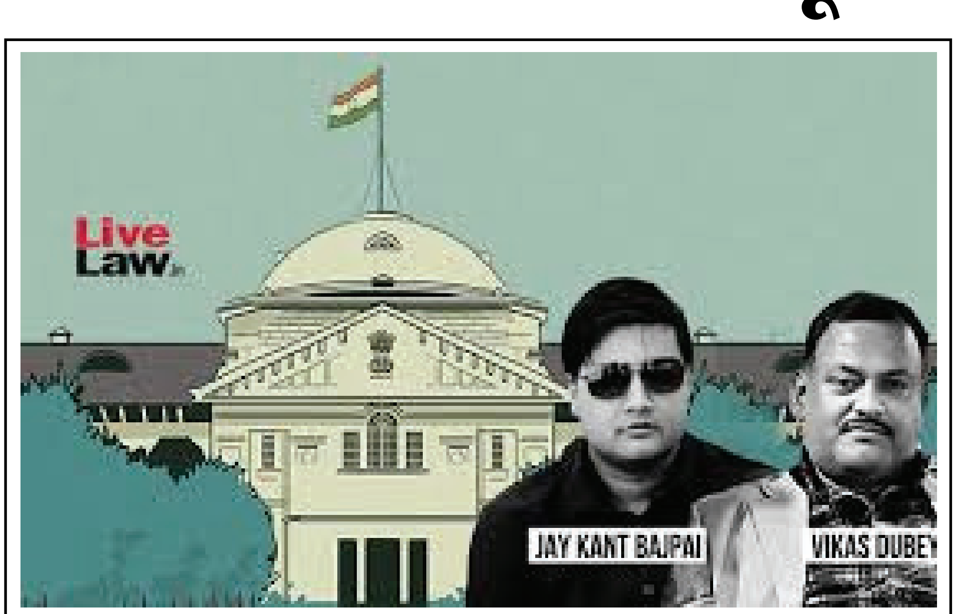

245 पट्टों की मूल पत्रावली बिल्हौर तहसील से गायब!

» 23 साल पहले भीटी सुज्जानिवादा गांव में हुए थे जमीन के पट्टे

आखिर जमीन खा गई या आसमान लील गया

तत्कालीन रजिस्ट्रार कानूनगो के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर

भाकियू के साथ पीड़ित लंबे समय से बैठे हैं धरने पर

डीएम ने बना रखी है तीन सदस्यों की जांच कमेटी

विकास दुबे के जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आता है भीटी गांव

स्वराज इंडिया ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। तहसील क्षेत्र के भीटी गांव की भूमि प्रबंधक समिति के प्रस्ताव द्वारा 23 साल पहले ढाई सैकड़ा किसानों को किए गए पट्टा आवंटन की पत्रावली गायब होने की घटना ने समूचे तहसील प्रशासन की कार्य प्रणाली पर कालिख पोत दी है। तहसील प्रशासन के निर्देश पर भले ही वर्तमान रजिस्ट्रार कानूनगो दिनेश कुमार ने अपनी गर्दन बचाने के लिए तत्कालीन रजिस्ट्रार कानूनगो मौजीलाल के एफआईआर दर्ज करवा दी है लेकिन इससे आवंटियों को भूमिधरी होने का हक मिल भी पाएगा, यह अभी भी भविष्य के गर्त में है।

जानकारी के मुताबिक कभी आतंक के पर्याय रहे बिकरू निवासी विकास दुबे के जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत भीटी सुज्जा निवादा गांव में ग्राम प्रधान की पहल पर 245 लोगों को कृषि भूमि का आवंटन किया गया था। 50 दिनों से धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी अनंत अवस्थी के मुताबिक सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह पट्टे पति और पत्नी दोनों के नाम किए गए थे। पट्टा आवंटन के बाद अधिकांश लोगों ने अपनी अपनी जमीन पर कब्जा कर खेती शुरू कर दी। दस वर्ष का समय बीत जाने के बाद कुछ लोगों ने तहसील के अधिकारियों कर्मचारियों से मिलीभगत करके अपनी भूमि असंक्रमणीय

से संक्रमणीय घोषित करा ली। जब इस बात की भनक दूसरे लोगों को हुई तो वह भी सक्रिय हुए लेकिन अधिकारियों ने उन्हें टके सा जवाब दे दिया। समय बीतने के साथ भारतीय किसान यूनियन ने मुद्दे को लेकर तहसील परिसर में धरना शुरू कर दिया। तहसील प्रशासन ने समझा बुझाकर मामला शांत करने की कोशिश की। लेकिन जिद्दी कार्यकर्ता नहीं माने। बीते दिनों समाधान दिवस में पहुंचे डीएम के सामने जब यह मामला पहुंचा तो उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए तीन पीसीएस अधिकारियों की एक कमेटी बना दी। जिसे 26 मई तक अपनी रिपोर्ट डीएम को देनी थी। लेकिन जांच और रिपोर्ट के नाम पर अभी तक क्या हुआ और यह अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि इसके बाद तहसील प्रशासन सक्रिय हुआ। और तत्कालीन रजिस्ट्रार कानूनगो मौजीलाल अपना पक्ष रखने बिल्हौर तहसील आए। वे प्रमाण सहित अपनी कोई बात नहीं रख पाए। अलबत्ता अपने कार्यकाल के दौरान उनका एसडीएम के जिन अहलमद राजेंद्र सिंह यादव से छत्तीस का आंकड़ा चलता था गेंद उनके पाले में फेंककर अपना दामन साफ बताने की कोशिश जरूर की।

कई गांवों में पट्टा आवंटन के नाम पर किया गया था खेल!

बिल्हौर। तहसील में कर्मचारियों द्वारा किए गए खेल की यह केवल बानगी भर है। यदि गहराई से पड़ताल की जाए तो कई गांवों की पट्टा आवंटन पत्रावलियां गायब ही मिलेंगी। इस बात की चर्चा लोगों की जुबान पर है। कुछ विवादित गांव सभाओं में मनमाने ढंग से किए गए पट्टे कल भी चर्चा में रहे थे और आज भी चर्चा में हैं। देखना यह है कि इन गांवों की पत्रावलियों का कला सच सामने कब आता है।

50 दिनों से राशन पानी के साथ बैठे हैं धरने पर

बिल्हौर। भाकियू के लोग जिस तरह से राशन पानी लेकर डेढ़ महीने से अपनी छह सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील में धरने पर बैठे हैं और यहीं पर बनाते खाते हैं। उससे जहां एक ओर वह प्रशासन पर दबाव बनाने में कामयाब रहे हैं वहीं दूसरी ओर इस बात को भी बल मिला है कि लोकतांत्रिक तरीके से सामूहिक रूप से कही गई बात भी अंजाम तक पहुंच सकती है।

एफआईआर दर्ज होने के बाद बिल्हौर तहसील में पहुंच कर अभिलेख देखते मौजीलाल

बिल्हौर तहसील परिसर में धरने पर बैठे भाकियू के लोग

नायब तहसीलदार पद से सेवानिवृत्त है मौजीलाल

बिल्हौर (कानपुर)। बिल्हौर तहसील में रजिस्ट्रार कानूनगो रहे मौजीलाल नायब तहसीलदार के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। बीते दिन जब उन्हें बिल्हौर तहसील आना पड़ा तो उनके चेहरे पर हवाइयां साफ दिख रही थीं। लेकिन आवंटन पत्रावली मिल भी पाएगी यह सवाल अभी भी बना हुआ है। हालांकि उन्होंने खुद को क्लीन चिट देने के लिए तहसील के अभिलेखों में काफी खोजबीन की। पत्रावली से आर 6 पर अमल दरामद मौजीलाल ने किया था। इसलिए उसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है।

मूल पट्टा आवंटन पत्रावली के बिना संक्रमणीय की कार्रवाई संभव नहीं- बलवीर सिंह एडवोकेट

बिल्हौर। बिल्हौर तहसील के अधिवक्ता बलवीर सिंह का कहना है कि बिना मूल आवंटन पत्रावली के असंक्रमणीय भूमि को संक्रमणीय करना विधिक रूप से गलत है। ऐसे में जिन किसानों को पट्टे पर भूमि मिली थी। उनको भूमिधरी घोषित करने की कार्रवाई करके कोई भी अपनी गर्दन नहीं बचाएगा।

ज़ब एसडीएम ने जूस पिलाकर खत्म कराई थी भूख हड़ताल

बिल्हौर। अपनी मांगो को लेकर दर्जनों किसानो के साथ धरने पर बैठ किसानों की आवाज बुलंद कर रहे किसान नेता अनंत अवस्थी कुछ दिन भूख हड़ताल पर भी बैठे थे। हालत ज्यादा बिगड़ने पर एसडीएम रश्मि लाम्बा प्रशासनिक अफसरों के साथ धरना स्थल पर पहुंची थी। और जूस पिलाकर भूख हड़ताल खत्म कराई थी। तकरीबन 50 दिन से अधिक हो गया लेकिन किसानों का धरना जारी है। अनंत अवस्थी का कहना है हमारी माँग पूरी हो जाए हम धरना खत्म कर देंगे।

केडीए की कल बोर्ड बैठक

कानपुर। कानपुर विकास प्राधिकरण की कल बोर्ड बैठक आयोजित हो रही है। वीसी मदन सिंह गर्ब्यांयाल ने बताया कि न्यू कानपुर सिटी परियोजना में आवासीय और कमर्शियल प्लॉट 14 सौ 2 हजार किए जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य बजट को लेकर चर्चा की जाएगी।

लाल इमली कर्मचारियों ने सांसद रमेश अवस्थी का किया भव्य स्वागत

प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। सांसद रमेश अवस्थी के निवास कार्यालय पर लाल इमली मिल के कर्मचारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर कर्मचारियों ने सांसद द्वारा संसद में उनके बकाया वेतन के मुद्दे को जोरदार ढंग से उठाने के लिए आभार व्यक्त किया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि रमेश अवस्थी जैसे सांसद अब तक नहीं देखे, जो खुद को न केवल जनप्रतिनिधि बल्कि कर्मचारियों के परिवार का सदस्य मानते हैं।कर्मचारी नेताओं ने सांसद के इस संवेदनशील रवैये की सराहना करते हुए कहा, रमेश अवस्थी जी ने हमारी समस्याओं को न सिर्फ समझा, बल्कि संसद में हमारी आवाज बनकर हमारे हक के लिए लड़ाई

» बकाया वेतन के लिए संसद में उठाई आवाज का जताया आभार

लड़ी। उनका यह प्रयास हमारे लिए गर्व का विषय है, जिसके बाद ही कर्मचारियों का वेतन आ सका। स्वागत समारोह में कर्मचारियों ने सांसद के प्रति अपनी एकजुटता और विश्वास जताया, साथ ही मिल के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की।सांसद रमेश अवस्थी ने इस दौरान आये सभी कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि वे उनकी हर समस्या के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। कर्मचारियों की समस्या स्वयं सांसद की समस्या है । लाल ईमली मिल कर्मचारियों द्वारा यह आयोजन न केवल कर्मचारियों और सांसद के बीच मजबूत रिश्ते को दर्शाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि जनप्रतिनिधि और जनता के बीच विश्वास

का रिश्ता कितना महत्वपूर्ण हो सकता है।

सेठ आनंदराम जैपुरिया स्कूल में समर कैंप की धूम

आओ हम सब मिलकर ग्रीष्म शिविर में धूम मचाएँ, खेल-खेल में सीख-सीख कर कुछ नया बनाए

स्वराज इंडिया संवाददाता

कानपुर। सेठ आनंदराम जैपुरिया स्कूल, कानपुर में 26 से 31 मई, 2025तक ग्रीष्म शिविर (समर कैंप) का आयोजन किया गया। जिसमें आई.सी.एस.ई के कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों एवं कैम्ब्रिज के छात्रों से जोश और उत्साह के साथ प्रतिभागिता की। ये गतिविधियों सामाजिक कौशल और भावनात्मक स्थिरता विकसिल करने में भी सहायक हैं। यह शिविर कक्षा एक से आठवीं कक्षा तक तथा कैम्ब्रिज के छात्रों के लिए था। दिन की शुरुआत प्रातः कालीन प्रार्थना सभा के साथ हुई, जिसके बाद वार्म अप व्यायाम और जुम्बा सेशन हुए। बच्चों ने नॉन-फायर कुकिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस वेस्टर्न एंड इंडियन, म्यूजिक वोकल, इंस्ट्रूमेंटल, कंप्यूटर लेगो और रोबोटिक्स के साथ स्पेस साइंस एक्टिविटी का अनुभव लिया।

कैम्ब्रिज के छात्रों तथा आई.सी.एस.ई के कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों ने इन गतिविधियों में बड़ी संख्या में उत्साहपूर्वक भाग लेकर समूह प्रदर्शन, चित्रकला और हस्तकला तथा गायन और नृत्यकला के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदर्शन के कौशल सीखे। कैम्ब्रिज के नन्हे-मुन्ने बच्चों ने विशेष रूप से गायन, नृत्य को खेल-खेल में सीखकर विज्ञान जैसे विषय में मानव शरीर रचना को गुब्बारे और क्यू टिप्स से बनाए गए फेफड़ो और कंकाल के मा डल के माध्यम से जीवंत किया। बिना आग के खाना पकाने के सत्रों ने रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच के साथ छात्रों ने विभिन्न व्यंजनों को बनाना सीखा।

लेगो बिल्डिंग ने उन्हें तार्किक रूप से सोचने और समस्याओं को हल करने की चुनौती दी जबकि लगोल विज्ञान ने ब्रह्मांड के बारे में जिज्ञासा जगाई।इन अनुभवों ने न केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा को बढ़ाया बल्कि प्रतिभागियों के बीच सामुदायिक भावना को भी बढ़ावा दिया।ग्रीष्म शिविर का समापन समारोह 31 मई, 2025 को आयोजित किया गया था। इस समारोह में विद्यालय के प्रधानाचार्य गणेश तिवारी, उपप्रधानाचार्य सीनियर स्कूल एम.के. मिश्रा, उपप्रधानाचार्या जूनियर स्कूल- मधुश्री भौमिक, जी एम शैलेंद्र अग्निहोत्री, कैम्ब्रिज समन्वयक अपर्णा चौहान, हेड मिस्टेक्स-श्रीमती शालिनी शुक्ला उपस्थित रहे।समारोह का शुभारम्भ छात्र वाद्य वृंद की मनमोहक प्रस्तुति के साथ हुआ, उनके प्रदर्शन से दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। शास्त्रीय तथा पाश्चात्य नृत्य प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। विभिन्न समूहों के छात्रों ने अपने सीले गए कौशल का प्रदर्शन किया और अपने अनुभव साझा किए। सभी ने पात्रों की गतिविधियों और सक्रिय भागीदारी की सराहना की।शिविर का समापन प्रधानाचार्य जी के ज्ञानवर्धक एवं आशीर्वचनों के साथ हुआ। उनके मधुर एवं प्रेरणादायी शब्दों ने छात्रों को इसी प्रकार अपनी योग्यता तथा बुद्धि के बल पर नए-नए रचनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया।

हलीम ग्राउंड पर आज से यूपी की सबसे बड़ी जानवरों की बाजार

स्वराज इंडिया संवाददाता

कानपुर। बकरीद के मौके पर चमनगंज स्थित हलीम कालेज ग्राउंड पर यूपी की सबसे बड़ी जानवरों की बाजार सोमवार से लगेगी। यहां कई जिलों व कस्बों से किसान, व्यापारी अपने जानवर लेकर खरीद-फरोख्त के लिए पहुंचने शुरु हो गए हैं।

रविवार को कई कस्बों व जिलों के व्यापारी अपने जानवर लेकर हलीम कालेज के पास पहुंचे लेकिन हलीम ग्राउंड पर जाने की इजाजत नहीं मिली जिससे जानवर हलीम कालेज के बाहर ही हैं। अबतक 500 जानवरों की खेप यहां पहुंच चुकी है।

हलीम कालेज में पिछले पांच वर्षों से बकरीद के मौके पर जानवरों की बिक्री होने लगी है, इसके पहले नई सड़क, बाकरगंज समेत कई स्थानों पर बकरों की बाजार लगती थी लेकिन अब हलीम कालेज सबसे बड़ी बाजार हो गई है। यहां छोटे बड़े सभी प्रकार के जानवर लाए जाते हैं।बताते चलें कि बकरीद का त्योहार तीन दिनों 7,8 व 9 जून को मनाया जाएगा जिसमें तीनों दिन अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी दी जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक अपने शहर में 7 जून को 3.5 लाख, 8 जून को 2 लाख और 9 जून को 80 हजार जानवर कुर्बान किए जाएंगे।

सामूहिक कुर्बानी भी की जाएगी

चमनगंज, जाजमऊ समेत शहर के कई क्षेत्रों में सामूहिक कुर्बानी की व्यवस्था की गई है, ये सामूहिक कुर्बानी उन लोगों के लिए है जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वे कोई जानवर खरीद सकें, ऐसे में सामूहिक कुर्बानी कराने वाले एक बड़े जानवर 7 लोगों को भागीदार बनाते हैं।

जामा मस्जिद शफियाबाद में दो बार नमाज

चमनगंज स्थित जामा मस्जिद शफियाबाद में ईद-उल-अजहा की नमाज दो बार अदा की जाएगी। इंतजामिया कमेटी जामा मस्जिद शफियाबाद के सदर जावेद कुरैशी ने बताया कि जामा मस्जिद शफियाबाद में 7 जून को पहली नमाज सुबह 7 बजे होगी और दूसरी नमाज सुबह 8.15 बजे अदा की जाएगी।

सम्पादकीय

सार्थक संवाद से सुलझेंगी समस्याएं

भारतीय किसान यूनियन के एक घटक द्वारा चंडीगढ़ में नये सिरे से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी के बाद पुलिस-प्रशासन की सख्ती से बुधवार को सामान्य जीवन व यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। चंडीगढ़ से लगते इलाकों में पुलिस के अवरोधों के चलते वाहन घंटों जाम में फंसे रहे। पुलिस आंदोलनकारियों से निबटने के लिये सख्त बनी रही और कई किसान नेताओं को गिरफ्तार किया गया। चंडीगढ़ के अनेक प्रवेश मार्गों को सील किया गया था और भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शुरू हुए आंदोलन से उपजे हालात पर आम लोग कहते रहे कि जाम किसानों की तरफ से है या सरकार की तरफ से। दरअसल, पंजाब जो लंबे समय से कृषि क्षेत्र में उदार दृष्टिकोण रखने वाला राज्य रहा है, तंत्र की संवेदनहीनता और शासन की सख्ती के चलते अशांत नजर आता है। भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसे कभी बदलाव का अग्रदूत कहा जाता था, अब खुद को प्रमुख हितधारकों-किसानों, राजस्व अधिकारियों और नौकरशाही के साथ उलझी हुई पा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि कहां कमी रही कि कृषि क्षेत्र अशांत बना हुआ है। समय रहते किसानों की मांगों को पूरा न किए जाने और कारगर समाधान के लिये परामर्श न मिल पाने से निराश किसान यूनियनों ने नये सिरे से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जिसकी परिणति 'चंडीगढ़ चलो मार्च' के रूप में सामने आई है। किसान नेता आरोप लगा रहे हैं कि किसानों की समस्याओं के समाधान पर संवेदनशील रवैया अपनाने के बजाय दमनात्मक कदम उठाये जा रहे हैं। जिसे वे देर रात छापेमारी करके किसान नेताओं की गिरफ्तारी और चंडीगढ़ की सीमाएं सील करने के रूप में देख रहे हैं। किसान नेता आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री मान ने किसानों की बैठक में से नाटकीय ढंग से वॉकआउट करके अपनी हताशा को ही जाहिर किया है।वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री का कहना है कि पंजाब में किसान संगठनों में आंदोलन करने की होड़ मची है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि पंजाब धरनों का राज्य बनता जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार जंग लड़ रही है। सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिये तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों सहित पंद्रह राजस्व अधिकारियों को निलंबित किया है। साथ ही अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन न करने वाले कई अन्य अधिकारियों का तबादला किया गया है। जिसके विरोध में राजस्व अधिकारियों ने तल्ख प्रतिक्रिया व्यक्त की। जिसके प्रत्युत्तर में राजस्व अधिकारियों ने सामूहिक अवकाश लेने का विकल्प चुना। जिसके चलते प्रशासनिक काम बुरी तरह प्रभावित हुआ। हालांकि, बुधवार शाम उन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। वैसे एक हकीकत यह भी है कि भले ही सरकार सख्त रवैया अपनाते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई के जरिये अपनी ताकत दिखा सकती है, लेकिन प्रणालीगत भ्रष्टाचार और नौकरशाही की नाराजगी की गहरी गुत्थी अभी भी अनसुलझी है। सवाल उठाया जा रहा है कि सरकार की यह सख्ती क्या हताशा का पर्याय है? वहीं प्रशासन का तर्क है कि लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन से बड़े निवेशक पंजाब में निवेश करने से कतरा रहे हैं। जिससे राज्य का आर्थिक विकास बाधित हो सकता है। लेकिन सवाल यह भी कि कृषि प्रधान राज्य क्या किसानों के हितों की अनदेखी कर सकता है? जिस तरह से लंबे समय से आंदोलनरत किसानों की मांगों के प्रति उदासीनता दर्शायी जा रही है, उससे किसानों की लोकतांत्रिक भागीदारी को लेकर चिंताएं पैदा होती हैं। निश्चित रूप से किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन के दमन से सामाजिक विभाजन और गहरा होता है। दरअसल, पंजाब का संकट सिर्फ हड़ताली अधिकारियों या फिर विरोध करने वाले किसानों को लेकर ही नहीं है। जो आंदोलनकारियों से सहज संवाद की कला को खोता प्रतीत हो रहा है। निश्चित रूप से अपने राज्य के लोगों के साथ सख्ती का व्यवहार तंत्र की नाकामी को ही उजागर करता है। निर्विवाद रूप से निराशाजनक वातावरण को यथाशीघ्र दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

कुपोषण से जंग जीतकर ही बनेगा विकसित भारत

विश्वनाथ सचदेव

हाल ही में बिहार में बहुतायत में पैदा होने वाले मखाने को लेकर खूब चर्चा हुई। इसे सुपरफूड बताया गया। लेकिन यह महंगा है और आम आदमी की पहुंच से दूर है। ध्यान रहे कि देश के लगभग एक-तिहाई बच्चों में खून की कमी है। 'नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे' के अनुसार 15 से 50 साल तक की आधी से अधिक लड़कियां-महिलाएं रक्त की कमी से त्रस्त हैं।कहते हैं राजनीति की दुनिया में कुछ भी कहा जा सकता है। इस दुनिया के हर प्राणी को यह विशेषाधिकार मिला हुआ है कि वह जो चाहे बोले, जो चाहे दावे करे। खास तौर पर चुनावों के मौकों पर तो कुछ भी कहने, दावा करने का यह अधिकार खूब काम में लिया जाता है। इस बात की एक विशेषता यह भी है कि राजनेताओं के कथनों-दावों की सत्यता की कोई शिनाख्त नहीं होती। जो नेता बोले, सो सच!

होता यह भी है कि नेता इन दावों-बातों को अक्सर भूल जाते हैं। कहना चाहिए, जान-बूझकर भुला दिया जाता है। फिर अगला चुनाव आ जाता है। फिर नये दावे, नयी बातें। कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक चुनाव में एक नेता जो बोलता है, वैसा ही कुछ दूसरे चुनाव में दूसरा नेता बोल जाता है। मज़े की बात यह है कि इसे भी राजनीति की एक ज़रूरत के रूप में स्वीकार कर लिया गया है।

यह सारी बातें जो आज याद आ रही हैं उनका रिश्ता मखानों से है। वैसे यह रिश्ता किसी भी 'नायाब' चीज़ से हो सकता है, पर फिलहाल यह सब मखानों के संदर्भ में याद आ रहा है। सब जानते हैं कि मखाने बहुत पौष्टिक होते हैं। सामान्यतः बड़े लोग, यानी धनी लोग ही इसका सेवन कर पाते हैं। वैसे, अक्सर उपवास आदि में ही मखाने ज्यादा खाये जाते हैं। ज्ञातव्य यह भी है कि मखाने मुख्य भोजन नहीं होते, नाश्ते के रूप में या नमकीन के रूप में ही इसका उपयोग हो पाता है। ऐसा इसलिए कि मखाना एक महंगा पदार्थ है। सुना है, बाज़ार में इसका भाव पंद्रह सौ से लेकर दो हजार रुपये प्रति किलो है। थोक भाव कुछ कम होता होगा।तो जैसा कि सब जानते हैं, यह बहुत महंगा और बहुत पौष्टिक आहार है। अब तो सब यह भी जान गये होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी को यह आहार बहुत पसंद है। हाल ही में जब वह आगामी चुनावों के संदर्भ में प्रचार करने के लिए बिहार गये थे तो वहां एक विराट जनसभा में उन्होंने बताया था कि वे साल के 365 दिनों में से 300 दिन तो वह मखाना खाते ही हैं। उनके अच्छे स्वास्थ्य का एक कारण यह आहार भी हो सकता है। उस सभा में प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि दुनिया के बाज़ार में इसकी मांग बढ़ती जा रही है। हमारे देश में बिहार राज्य में इसकी सर्वाधिक पैदावार है। देश में मखाने की उपज का लगभग 35 प्रतिशत बिहार में ही होता है। कहते हैं 25-30 हजार किसान परिवार इस खेती से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मखाने की मांग को ध्यान में रखते हुए हमारे बिहार के किसान भी इससे लाभ उठाएं-उन्होंने कहा है, 'अब मखाने को दुनिया के बाज़ार तक पहुंचाना है।' उस सभा में तालियां बजाकर प्रधानमंत्री की इस बात का स्वागत किया गया था। तबसे देशी बाज़ार में भी मखाना चर्चा में है। अब इसे 'सुपरफूड' भी कहा जाता है। अंग्रेजी के इस विशेषण से हमारा मखाना और महत्वपूर्ण हो गया है।इस सुपरफूड की चर्चा देश के मुख्य धारा के समाचार-चैनलों में खूब हुई है। चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है, पर वहां स्वर कुछ अलग है। वहां इस बात पर हैरानी तो व्यक्त नहीं की जा रही, पर यह ज़रूर कहा जा रहा है कि इतना महंगा 'सुपरफूड' प्रधानमंत्री ही, या फिर उनका मित्र-परिवार भी, साल में 365 में से 300 दिन ही तक खा सकता है! सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि जिस देश में 80 करोड़ आबादी को मुफ्त अनाज देकर पेट भरवाना पड़ रहा हो, वहां का आम आदमी इतना महंगा 'सुपरफूड' कैसे खा सकता है?बहरहाल, आज भले ही यह दावा किया जा रहा हो कि 21वीं सदी भारत की है और 2047 तक हमारा भारत एक विकसित देश बन जाएगा, पर आज की स्थिति तो यही है कि हमारे देश में जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा। वर्ष 2024 के ही एक सर्वेक्षण के अनुसार 'भुखमरी इंडेक्स' में दुनिया के 127 देशों में हमारा स्थान 105वां है। हम यह दावा करते फिरें कि हमारा भारत जल्द ही विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ जायेगा, पर हकीकत यह है कि अभी हम अपनी भूख मिटाने लायक भी नहीं बने हैं। जल्दी ही हम विकासशील देश से विकसित राष्ट्र बन जायें, यह कौन नहीं चाहेगा, पर चाहना हमें यह भी होगा कि वह दिन शीघ्र आये जब देश की आम जनता भी मखाना जैसा महंगा अनाज खा सके। मखाने का स्वाद उसे भी पता हो।अभी तो यह बात एक खुशफहमी ही लगती है। हमें इस बात को भी नहीं भुलाना होगा कि वर्ष 2025 के एक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में 28 राज्यों में बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। देश के लगभग एक-तिहाई बच्चों के शरीर में खून की कमी है। महिलाओं की स्थिति इन बच्चों से भी बुरी है।

नई व्यापार रणनीति से मुकाबले की कोशिश

टैरिफ वार

जयंतीलाल भंडारी

अमेरिका के टैरिफ वॉर के मुकाबले के लिए भारत की नई द्विपक्षीय व्यापार वार्ताएं एक असरकार हथियार है। भारत के लिए ट्रंप की चुनौतियों के बीच वैश्विक कारोबार के नए अवसर भी निर्मित हो रहे हैं। इससे भारत को वैश्विक निर्यात में भी बढ़त मिल सकती है।हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा और मैक्सिको पर 25 फीसदी और चीन के आयात पर भी 10 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ प्रभावी किए जाने के बाद इन देशों ने भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाए हैं।

अब भारत भी टैरिफ वृद्धि के मद्देनजर अमेरिका के निशाने पर है। जहां भारत में अमेरिकी टैरिफ से टेक्सटाइल, दवाई, ऑटोमोबाइल, इस्पात, एल्युमीनियम और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर्स में चिंताएं हैं, वहीं हमारे शेयर बाजार के दोनों सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी बड़ी गिरावट के दौर में हैं। ऐसे में भारत अमेरिका के लिए उपयुक्त टैरिफ रियायतों की नई रणनीति के साथ द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं की ट्रंप की टैरिफ मार से मुकाबला करने को सुनियोजित रूप से आगे बढ़ रहा है। खास बात यह भी है कि जहां अमेरिका से निर्मित टैरिफ चुनौतियों के बीच अब भारत को निर्यात के नए मौके मिलने की उम्मीद है, वहीं ट्रंप की नीति से भारत को चीन प्लस वन के रूप में दुनिया के वैश्विक व्यापार में तेजी से बढ़ने का मौका भी मिलते हुए दिखाई दे सकेगा। चार मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया का हर देश भारत के साथ आर्थिक कारोबारी साझेदारी मजबूत करना चाहता है। हमारे उद्योग-कारोबार क्षेत्र को नए मौके हासिल करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।दरअसल, ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट और रेसिप्रोकल टैरिफ की नीति के कारण दुनिया में तेजी से आर्थिक और कारोबारी उठापटक चल रही है। नया व्यापार युद्ध शुरू हो गया है। वैश्विक व्यापार नए सिरे से दोबारा स्थापित होने

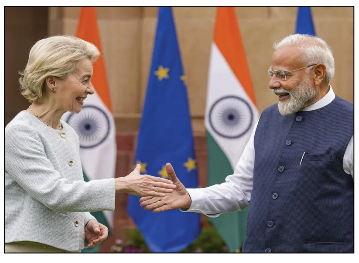

जा रहा है। विश्व व्यापार संगठन अब मुख्य स्तम्भ के रूप में नहीं बचा है और सबसे पसंदीदा राष्ट्र (एमएफएन) के दर्जे के तहत गैर-भेदभावपूर्ण शुल्क खत्म हो रहे हैं। ऐसे में भारत ने रणनीतिपूर्वक एक अप्रैल से प्रभावी होने वाले वर्ष 2025-26 के बजट में अमेरिका से आने वाली वस्तुओं जैसे महंगी मोटरसाइकिल, सैटेलाइट के लिए ग्राउंड इंस्टॉलेशन और सिंथेटिक फ्लेवरिंग एसेंस जैसे कुछ सामानों पर शुल्क घटा दिए हैं। साथ ही मित्र देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) की ऐसी नई रणनीति पर आगे बढ़ा है, जिसमें मित्र देशों को पर्याप्त रियायतें भी हैं।

इसी परिप्रेक्ष्य में विगत 28 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी और यूरोपीय आयोग (ईयू) की प्रेसिडेंट उर्सला वोन लेयेन ने दोनों पक्षों के बीच कारोबार एवं आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए मुक्त व्यापार समझौता को लेकर जारी किंतु-परंतु को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। दोनों नेताओं ने प्रतिबद्धता जताते हुए अपने संबंधित मंत्रालयों को निर्देश दिया कि दोनों पक्षों के हितों के मुताबिक भारत-ईयू व्यापार समझौते पर इस वर्ष 2025 के अंत तक मुहर लगाई जाए। उल्लेखनीय है कि विगत 13 फरवरी पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप के बीच हुई वार्ता के दौरान द्विपक्षीय कारोबार को वर्ष 2030 तक 500 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। पिछले माह फरवरी में भारत के दौरे पर आए ब्रिटेन के व्यवसाय व कारोबार मंत्री जोनाथन रेनाल्ड्स ने कहा कि व्यापारिक समझौते का उद्देश्य पांच से छह वर्षों में द्विपक्षीय कारोबार को तीन गुना करना है। इसी तरह अमेरिका और ब्रिटेन के साथ भी मुक्त व्यापार व निवेश समझौते को इसी साल 2025 में पूर्ण किए जाने के मद्देनजर भी भारत ने रणनीति तय की है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका, यूरोपीय आयोग और ब्रिटेन इन तीनों का भारत के कुल द्विपक्षीय वैश्विक कारोबार में एक-तिहाई से भी ज्यादा का हिस्सा है। निश्चित रूप से इस समय ट्रंप के टैरिफ तूफान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं की ऐसी डगर को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, जो उन्होंने तीसरे कार्यकाल से ही लगातार आगे बढ़ाना शुरू किया है। निस्संदेह, अमेरिका के टैरिफ वार के मुकाबले के लिए भारत की नई द्विपक्षीय व्यापार वार्ताएं भारत का एक असरकार हथियार है। भारत के लिए ट्रंप की चुनौतियों के बीच वैश्विक कारोबार के नए अवसर भी निर्मित हो रहे हैं। इन क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल उपकरण, मोबाइल फोन, फुटवीयर, टेक्सटाइल और गार्मेंट्स, फर्नीचर और घर के सजावटी सामान, वाहनों के कल पुर्जे, खिलौने और रसायन आदि शामिल हैं।इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में पहुंच बढ़ाने के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में स्वीकृत किया गया ।

प्रधान और सचिव ने गरीबों के हक पर डाला डाका!

शिवांक अग्निहोत्री/ स्वराज इंडिया

कानपुर नगर। चौबेपुर ब्लाक अंतर्गत ग्राम पंचायत चिंता पूरवा के जोगिन डेरा में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। आरोप है कि लाभार्थियों को आवास मिलने के बावजूद ग्राम प्रधान धनीराम कुशवाहा और पंचायत सचिव ने मिलकर आवास की सरकारी किस्त में से पैसे वसूले। एक गरीब महिला ने जब पैसे देने से इनकार किया तो प्रधान द्वारा मारपीट का भी आरोप लगाया गया है। यह सब मोदी सरकार की ड्रीम योजना में हो रहा है, जिसे गरीबों को पक्का मकान दिलाने के लिए शुरू किया गया था।

शौचालय योजना में भी घोटाला, ठेकेदार के भरोसे अधूरे काम

» प्रधानमंत्री आवास और शौचालय योजना में खुलेआम लूट, पीड़ित महिला ने लगाए गंभीर आरोप

प्रधानमंत्री आवास की किस्त के नाम पर वसूली, विरोध पर मारपीट

गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालय केवल कागजों पर ही पूरे हैं। जोगिन डेरा के पूरे जोगी समुदाय में एक भी शौचालय कार्यरत नहीं है। ठेकेदारों के जरिए अधूरे ढांचे खड़े कर रिपोर्ट में पूरा कार्य दिखाया गया है। बिना प्लास्टर और रंगाई के शौचालयों का भुगतान निकालना मामले को और भी संदिग्ध बनाता है। यदि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो बड़े पैमाने पर घोटाले का पर्दाफाश हो सकता है। अब देखना है कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है।

एमईएस बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का चुनाव सपन्न

स्वराज इंडिया संवाददाता

कानपुर। एमईएस बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हर 2 वर्ष में होने वाले चुनाव का आयोजन गगन प्लाजा होटल माल रोड पर किया गया। अध्यक्ष और महामंत्री के साथ अन्य पदों पर भी चुनाव हुए, जहां अनिल त्यागी को अध्यक्ष पद पर वही नवीन कुमार यादव को सेक्रेटरी चुना गया, कैशियर पद पर परविंदर सिंह संधू का चुनाव हुआ, काउंसिल मेंबर्स में रतन पांडे, अमिताभ पांडे, दीपक भाटिया और विपिन आनंद चुने गए, इलेक्शन कमिश्नर जेपी पांडे और कामरान खान की अध्यक्षता में चुनाव की पूरी कार्यवाही संपन्न हुई, जहां मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी मन्नू महाना भी मौजूद रहे,महामंत्री नवीन यादव ने कहा की लंबे समय से ठेकेदार पेमेंट जैसी कई समस्याओं को लेकर परेशान रहते हैं, नई कार्यकारिणी के चुनाव के बाद ऐसी सभी समस्याओं को लेकर आवाज उठाई जाएगी और भविष्य में हर समस्या की लड़ाई पुरजोर तरह से लड़ी जाएगी ।

बिठूर पुलिस को मिली बड़ी सफलता

» मादक पदार्थों और अवैध असलहों की तस्करी करने वाले दो शातिर आरोपियों को किया गिरफ्तार

मुख्य संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। अपराध शाखा स्वाट टीम और बिठूर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मादक पदार्थों और अवैध असलहों की तस्करी करने वाले दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नशे का सामान और हथियार बरामद किए हैं।पुलिस के अनुसार, पकड़े गए आरोपियों के पास से 27.50 ग्राम स्मैक (अनुमानित कीमत ?2.50 लाख), 920 ग्राम चरस (अनुमानित कीमत ?50 हजार) और दो 32 बोर की हैंडमेड पिस्टलें (बाजारू कीमत लगभग ?1.50 लाख) बरामद की गई हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी बड़े पैमाने पर नशे और हथियारों की खरीद-फरोख्त कर कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में ऊंचे दामों पर सप्लाई करते थे।

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वे स्मैक बाराबंकी (टिकरा) और चरस प्रयागराज के आसपास के क्षेत्रों से खरीदकर लाते थे। वहीं अवैध पिस्टलें बिहार के मुंगेर और आसपास के जिलों से मंगाई जाती थीं। आरोपी अब तक 10 से अधिक बार कानपुर आकर मादक पदार्थ और असलहों की सप्लाई कर चुके हैं।गिरफ्तार मुख्य आरोपी बलराम राजपूत पर पहले से ही विभिन्न थानों में गंभीर धाराओं में 9 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस इनके आपराधिक इतिहास और नेटवर्क की गहन जांच कर रही है।डीसीपी क्राइम एसएम कासिम आबिदी ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपी लंबे समय से इस अवैध

कारोबार में सक्रिय हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड की कोर्ट से मांग करेगी ताकि इनके पूरे नेटवर्क और गिरोह का पर्दाफाश कर सख्त कार्रवाई की जा सके।

नार्थ स्टार हॉस्पिटल के डॉ. अभिषेक त्रिवेदी ने बनाया कीर्तिमान

स्वराज इंडिया संवाददाता

कानपुर। आर्थोपेडिक्स के क्षेत्र में मशहूर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉ0 अभिषेक त्रिवेदी द्वारा नार्थ स्टार हॉस्पिटल में 70 वर्षीय लखनऊ निवासी राजेश सक्सेना जिनकी पूर्व में कैंसर होने के कारण जांघ की पूरी हड्डी खराब हो गई थी, जिसके कारण इनका चलना फिरना भी बंद हो गया था। नार्थ हॉस्पिटल में डॉ0 अभिषेक

» मरीज की कूल्हे से लेकर घुटने तक पूरी जांघ बदली

त्रिवेदी द्वारा कूल्हे से लेकर घुटने तक पूरी जांच बदल कर एक विशेष कीर्तिमान बनाया गया, इस तरह की जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक करने वाले डॉ0 अभिषेक त्रिवेदी उत्तर प्रदेश के एक मात्र आर्थोपेडिक्स सर्जन बन चुके है, इससे पहले यह विशेष सर्जरी उत्तर प्रदेश में कभी ना किसी हॉस्पिटल में ना ही किसी अर्थोपेडिक्सर सर्जन द्वारा करी गई है।

अभी तक इस तरह की सर्जरी के लिए लोगों को बड़े शहरों की राह देखनी पड़ती थी, परन्तु अब डॉ0 अभिषेक त्रिवेदी द्वारा इस नर्जरी को सफलतापूर्वक करने के पश्चात लोगों में नई उम्मीद उत्पन्न हो गई है कि कैंसर अथवा अन्य किसी कारण से कोई हड्डी खराब हो जाती है तो अब अपने ही उत्तर प्रदेश के आर्थोपेडिक्स सर्जन अथवा हॉस्पिटल में सर्जरी करवा कर उनके चलने की उम्मीद बनी रहेगी।

मकनपुर चौकी में पीस कमेटी की बुलाई गई बैठक

स्वराज इंडिया संवाददाता

बिल्हौर। सोमवार को अरौल इंस्पेक्टर ने मकनपुर चौकी पर बकरीद त्योहार को लेकर पीस कमेटी के सदस्यों की बैठक बुलाई।

बैठक में इंस्पेक्टर जनार्दन सिंह यादव ने बकरीद त्योहार को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। उन्होंने त्योहार को शांतिपूर्वक मनाए जाने की अपील की। कहा त्योहार में अफवाह फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अराजक तत्वों पर नजर बनाए हुए है। पीस कमेटी के सभी

» थानेदार बोले त्योहार पर अराजकता फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई

» त्योहार को शांतिपूर्वक तरीके से मनाने की अपील की

सदस्यों ने पुलिस के सामने अपनी अपनी बातें रखी। इस दौरान चौकी इंचार्ज मकनपुर, पुलिस कर्मी समेत क्षेत्र के संभ्रांत लोग मौजूद रहे।

वारदात के तीन दिन बाद भी पुलिस खाली हाथ

स्वराज इंडिया संवाददाता

बिल्हौर (कानपुर)। बीती 31 मई की रात बिल्हौर कोतवाली क्षेत्र में पांच घरों मे हुई चोरी की वारदात में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। हालांकि पुलिस जल्द घटना का खुलासा करने का दावा कर रही है।मालूम हो कि बिल्हौर कोतवाली क्षेत्र के माखनपुरवा गांव में चार व तरऊपुरवा गांव के एक घर में तीन दिन पहले रात को चोर फ़िल्मी स्टाइल से छत के रास्ते घर में दाखिल हुए और नकदी व जेवर पर अपना हाथ साफ कर फरार हो गए। सुबह घटना की जानकारी होने पर डीसीबी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी मौके पर पहुँचे और जांच पड़ताल की। उन्होंने पीड़ित परिजनों को जल्द से जल्द घटना

» 31 मई की रात चोरों ने पांच घरों में चोरी की वारदात को दिया था अंजाम

माखनपुरवा व तरऊपुरवा गांव में हुई थी लाखों की चोरी

घर के किसी भी सदस्य को चोरी की भनक तक नहीं लगी

का खुलासा करने का आश्वासन दिया था। लेकिन वारदात के तीन दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं।इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज ने बताया पुलिस टीमें लगी हैं। जल्द ही घटना का खुलासा किया जायेगा।

घर में चोरी हो गई और परिजनों को भनक तक नहीं लगी

जिस वक्त चोर छत के रास्ते से घर में आसानी से दाखिल हुए और चोरी भी कर ले गए। उस वक्त परिजन घर के बाहर सो रहे थे। ये बात परिजनों ने पुलिस को बताई। अब सवाल यह है कि क्या परिजनों को चोरी की जरा सी भी भनक तक नहीं लगी । अमूमन जोरदार आवाज होने पर लोगों की नींद खुल जाया करती है।

सूखी माइनरों से तड़पते खेत, समिति के बिना बेहाल किसान

सचिन सिंह स्वराज इंडिया

» गंगनहर विभाग की लापरवाही से मोहाना, जमरेही, पृथ्वीपुरवा के किसानों पर संकट

कानपुर देहात। गंगनहर विभाग की कार्यशैली पर किसान सवाल खड़े कर रहे हैं। माइनरों में पानी न पहुंचने से मोहाना, जमरेही, पृथ्वीपुरवा, विजयनगर समेत कई गांवों के खेत सूखे पड़े हैं। किसानों का आरोप है कि गंगनहर विभाग टेबल पर रखे कागजों में पानी चला रहा है, लेकिन हकीकत में माइनरों तक एक बूंद पानी नहीं पहुंच पा रही है। समिति के अभाव में माइनरों की देखरेख नहीं हो पा रही है। ठेकेदार मनमानी तरीके से सफाई कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि पहले जब माइनरों में समितियां सक्रिय थीं, तो बंधे नहीं बनते थे और न ही मिट्टी की अवैध खुदाई होती थी। अब हालत यह है कि अधिकतर माइनरों में समिति के सदस्य ही नहीं बचे हैं, जिससे अव्यवस्था चरम पर है।

पानी नहीं... जेब से पैसा जा रहा, भावुक हुए किसान

धान की बुवाई का समय सिर पर है, लेकिन किसान पानी के लिए तरस रहे हैं। जमरेही, मोहाना और विजयनगर गांव के युवा किसान शिवदीप मिश्रा, गोलू दीक्षित, अभिषेक और उदल ने रोते हुए बताया कि आंधियों में बिजली के पोल गिर जाते हैं और समय पर प्राइवेट पंपों से भी सिंचाई नहीं हो पाती। मजबूरी में पैसे खर्च कर बार-बार प्राइवेट ट्यूबवेल से पानी लेना पड़ता है।

किसानों का कहना है कि जमरेही माइनर में तो वर्षों से पानी नहीं आया, फिर भी सरकार हर साल सफाई पर पैसा खर्च करती है।

पहले की समितियां सक्रिय थीं तो स्थिति ठीक थी, अब ठेकेदारों की मनमानी और अधिकारियों की चुप्पी किसानों की जेब भी ढीली कर रही है और खेत भी सूखे पड़े हैं।

जवाबदेही

सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता सार्थक सिंह ने कहा कि जहां भी समस्या है, उसे दिखवाया जाएगा और समाधान किया जाएगा।

माइनर में पानी सिर्फ कागजों में, जेब से बह रहा पसीना

मोहाना गांव के युवा किसान गोलू दीक्षित का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा,हम लोग अपने ट्यूबवेल से ही सिंचाई करते हैं, माइनर में कभी पानी आता ही नहीं है। अगर समिति के सदस्य सक्रिय होते तो आज इन माइनरों पर पानी जरूर होता। हमें मजबूरी में प्राइवेट ट्यूबवेल से पानी खरीदकर खेत सींचना पड़ता है, जिससे जेब ढीली हो जाती है। अधिकारी सिर्फ कागजों पर पानी दिखाते हैं, जमीनी हकीकत कोई नहीं देखता। हम किसानों को देखने-सुनने वाला कोई नहीं है।फगोलू की बात न केवल मोहाना के किसानों की पीड़ा है, बल्कि जिले भर में पानी को लेकर जूझ रहे किसानों की सामूहिक आवाज़ है।

माइनरों से सालों से नहीं देखा पानी, खेती बन गई है महंगी मजबूरी

जमरेही कोरारी गांव के किसान विनय सिंह चौहान ने माइनरों की बदहाली पर गहरी नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा,फकिसानों के लिए पानी सबसे बड़ी समस्या बन गया है। हमें हर बार महंगे दाम पर प्राइवेट ट्यूबवेल से सिंचाई करनी पड़ती है। विभाग इस गंभीर मुद्दे पर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। अगर माइनरों की सही से सफाई और रखरखाव हो जाए, तो शायद खेतों तक पानी पहुंच सके। पहले जो समितियां बनाई गई थीं, उनके सदस्य माइनरों की देखरेख करते थे, इसलिए पानी की समस्या नहीं होती थी। लेकिन अब तो हालत ये है कि चाहे धान बोना हो या गेहूं–माइनर से पानी मिलना तो दूर, सालों से खेतों में माइनर का पानी देखा ही नहीं है।

विनय सिंह की बात से स्पष्ट है कि माइनरों की उपेक्षा सीधे किसानों की आजीविका पर चोट कर रही है। अगर समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, तो हालात और गंभीर हो सकते हैं।

20 साल की बेटी ने तोड़ा सांसों का रिश्ता, फांसी लगाकर दी जान

कानपुर देहात के अकना गांव में युवती ने घर के अंदर लगाई फांसी, जांच में जुटी पुलिस

स्वराज इंडिया ब्यूरो

कानपुर देहात। मंगलपुर थाना क्षेत्र के अकना गांव में सोमवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। गांव निवासी 20 वर्षीय प्रियांशी ने अपने घर में दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि प्रियांशी ने कमरे की दीवार पर लगी खूंटी से दुपट्टे का फंदा बनाकर जान दे दी।

घटना का पता चलते ही परिजनों ने उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हवासपुर पहुंचाया, जहां चिकित्सक डॉ. गौरव पॉल ने उसे मृत घोषित कर दिया।

प्रियांशी के पिता रामकिशोर कठेरिया, मां संध्या देवी, भाई मोहित और रोहित तथा बहन नैन्सी इस घटना से गहरे सदमे में हैं। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। संपादकः अनूप कुमार RNI No.: UPHIN/2023/86769 | Email: swarajindia2023@gmail.com | Mob: 7800009853, | Website: www.swarajindianews.com | (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

डीपीआरओ विकास पटेल पर हाईकोर्ट आदेश की अवहेलना, पंचायत सचिव को कराया फर्जी भुगतान

» एडवोकेट शहाबुद्दीन अली अहमद ने पंचायती राज मंत्री से की शिकायत, कार्रवाई और एफआईआर की मांग

» बिना पक्ष सुने की गई कार्रवाई, न्यायालय के आदेश को भी नजरअंदाज किया

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। संदलपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत ररौख में जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) विकास पटेल पर गंभीर आरोप लगे हैं।

एडवोकेट शहाबुद्दीन अली अहमद ने बताया कि त्रासदी समिति अध्यक्ष अंजू मिश्रा के खिलाफ बिना पक्ष सुने डीपीआरओ ने शिकायतकर्ता मुलायम सिंह के आधार पर टीम गठित कर दी। जबकि माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज ने 15 मई 2025 को आदेश पारित किया था कि मामले की दोबारा जांच कर छह सप्ताह में निर्णय लिया जाए।

यह आदेश 19 मई को डीपीआरओ कार्यालय में रिसीव भी हो गया था, लेकिन तीन सप्ताह बीत जाने के बाद भी आदेश का पालन नहीं किया गया।

फर्जी भुगतान का आरोप, कार्रवाई और वसूली की मांग

एडवोकेट शहाबुद्दीन अली अहमद ने आरोप लगाया कि डीपीआरओ ने आदेश की अनदेखी करते हुए 29 मई 2025 को पंचायत सचिव अजय कुमार को लगभग दो लाख रुपये का भुगतान आदेशित करवा दिया, जबकि जिस कार्य के नाम पर भुगतान हुआ, वह पंचायत में हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिव और अवैध रूप से खुद को समिति अध्यक्ष बताने वाले मुलायम सिंह द्वारा यह राशि निकाली गई है और आगे और भुगतान कराने की भी योजना है। उन्होंने जिला पंचायत राज अधिकारी और सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, सरकारी धन की वसूली करने और मुख्य पंचायत सचिव अनिल कुमार (आईएएस) से मामले की निगरानी की मांग की है।

वर्षाकाल 2025 में मिशन हरियाली रोपे जाएंगे 57.22 लाख पौधे

» कानपुर देहात में वन विभाग सहित 24 विभाग करेंगे सामूहिक पौधरोपण, कंट्रोल रूम से होगी मॉनीटरिंग

»वन विभाग की बड़ी तैयारी, नर्सरियों में तैयार हैं 71.57 लाख पौधे

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। शासन के निर्देश और जिलाधिकारी आलोक सिंह के मार्गदर्शन में वर्षाकाल 2025 के दौरान कानपुर देहात में 57.22 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया जाएगा। वन विभाग सहित 24 विभाग इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। प्रभागीय वनाधिकारी ए.के. द्विवेदी ने बताया कि सभी विभाग अग्रिम मृदा कार्य में जुटे हैं, जिसकी मॉनीटरिंग कंट्रोल रूम के ज़रिये निरंतर की जा रही है। इसके अलावा, वन विभाग की विभिन्न नर्सरियों में 71.57 लाख पौधों का उत्पादन किया गया है, जो जून तक रोपण योग्य आकार में आ जाएंगे।

हर पंचायत में बनेगा ग्रीन चौपाल, पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा नया आधार

शासन की मंशा के तहत हर ग्राम पंचायत में ग्रीन चौपाल का गठन किया जाएगा। इसका उद्देश्य पौधरोपण के साथ-साथ पर्यावरण, जल, वन्यजीव और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना है। ग्रीन चौपाल में ग्राम प्रधान, वन अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत सदस्य (कम से कम एक महिला), स्वयं सहायता समूह की महिला प्रतिनिधि, शिक्षक, आंगनबाड़ी सहायिका, प्रगतिशील कृषक और स्थानीय एनजीओ प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। गठन के बाद ग्रीन चौपाल का आयोजन कर पौधरोपण व जनजागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। साथ ही ग्राम्य विकास विभाग द्वारा 62 ग्राम पंचायतों में ग्राम वन विकसित किए जाने की योजना भी तैयार की जा चुकी है, जिनमें फलदार, छायादार व पर्यावरणीय प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे।

डीजे में नाच रही महिलाओं का वीडियो बनाने पर चले डंडे

» एक-दूसरे के घर में घुसकर लाठी-डंडे, ईंट-पत्थर से हमला बोला गया

» महिलाओं सहित एक दर्जन लोगों को चोट आईं

स्वराज इंडिया संवाददाता

सूरतगंज(बाराबंकी) । कुतुलूपुर गांव में कुंआ पूजन के दौरान डीजे पर डांस कर रही युवतियों और महिलाओं का वीडियो बनाएं जाने की बात को लेकर दो पक्षों में जबरदस्त वाद-विवाद हो गया।एक-दूसरे के घर में घुसकर लाठी-डंडे, ईंट-पत्थर से हमला बोला गया।उधर महिलाओं सहित एक दर्जन लोग को चोटे आई है। वायरल हुए वीडियो का संज्ञान लेकर दो घंटे बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है।

मोहम्मदपुर खाला थाना के ग्राम पंचायत उमरी के कुतुलूपुर निवासी, शीतल कोरी के बेटे अजय के घर में शादी की खुशियां थी।रविवार के शाम बारात विदाई से पूर्व गांव के बाहर, कुंआ पूजन कार्यक्रम चल रहा था।युवतियां और महिलाएं नृत्य कर रही थी।शीतल का आरोप है, कि गांव के आदेश तिवारी व उसका साला अनिकेत, प्रदीप तिवारी व विष्णु तिवारी कुछ अन्य साथियों के साथ वीडियो बना रहे थे।

जब महिलाओं ने मना किया, तो विवाद करने लगे। किसी तरह विवाद शांत हुआ, सभी बाराती चले गए।

महिलाएं व युवतियां भी घर चली गई। तभी देर रात्रि आदेश पिता राम निवास, प्रदीप, विष्णु और अनिकेत सहित आधा दर्जन लोग घर पहुंचे।मंगल कार्यक्रम में व्यस्त महिलाओं व युवतियों पर लाठी-डंडे से हमला बोल दिया। वहीं हमले में नीता, सनसनी, रोली आदि को चोटे आई। इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें कुछ महिलाएं अचेत अवस्था में पड़ी हुई।रविवार की दोपहर बारात वापस आई, तब पुरूषों का रात्रि की घटना के बारे में जानकारी हुई।तभी आक्रोशित शीतल,अर्जुन,संगम, अनुज, गुड्डू, दुलारे आदि दर्जनों लोग लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर लेकर राम निवास के घर पर पहुंच गए।हमला बोल आदेश उसके साले अनिकेत, प्रदीप,विष्णु,रामनिवास आदि की पिटाई करके घायल कर दिया। राम निवास तिवारी के घर की महिलाओं ने छत में चढ़ गांव वालों से गुहार लगाई।

उधर गांव वालों के एकत्र होने पर शीतल अपने अन्य साथियों के संग में भाग खड़े हुए। जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होते, ब्राह्मण समाज में आक्रोश व्यप्त हो गया है।

दोनों घटना पर डायल 112 की पीआरवी भी पहुंची। स्थानीय पुलिस के लापवाही से लोगों में आक्रोश फैला हुआ है। उधर इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक जगदीश प्रसाद शुक्ला ने बताया कि छानबीन की जा रही। दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

चौथे बड़े मंगल पर भंडारे का हुआ आयोजन

स्वराज इंडिया संवाददाता

बाराबंकी। लोनी कटरा क्षेत्र के भिलवल हनुमान मंदिर में ज्येष्ठ के चौथे बड़े मंगल पर भंडारे का आयोजन किया गया। भाजपा नेता अम्बर शरण जायसवाल की अध्यक्षता में एक दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो गई थीं।

दोपहर 12 बजे से पूर्व जिला पंचायत सदस्य शशि प्रभा, भाजपा नेता अम्बर शरण जायसवाल और सुशील पटेल लंबरदार ने हनुमान जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर ज्योति प्रज्वलित की। इसके साथ ही भंडारे की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में भाजपा विधायक दिनेश रावत और जिलाध्यक्ष सहित कई प्रमुख नेताओं ने शिरकत की।भंडारे में छोला, चावल, पूड़ी, पनीर, बूंदी, शीतल पेय और पाना सहित विभिन्न व्यंजन परोसे गए। भाजपा नेता सुशील पटेल, अरुण शुक्ला और दिलीप पटेल ने बताया कि दोपहर से ही भक्तों की कतार लगी रही। त्रिवेदीगंज क्षेत्र में इतने बड़े स्तर का यह अनूठा भंडारा था।

अम्बर शरण जायसवाल ने बताया कि यह भंडारा कई वर्षों से निरंतर आयोजित किया जा रहा है। हजारों की संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया

दूल्हा पक्ष वालों ने मांगे ढाई लाख रूपये, पुलिस तक पहुंचा मामला

हाथापाई के नौबत को देखते हुए किसी ने पुलिस ने पहुंच कर मामला शांत कराया

स्वराज इंडिया संवाददाता

बाराबंकी। क्षेत्र में बारात आने के बाद दूल्हा पक्ष वालों ने, ढाई लाख रूपये की मांग रख दी। विरोध करने पर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया।वहीं हाथापाई के नौबत को देखते हुए किसी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद में रात्रि को शादी की रस्में पूरी हुई है। सुबह बारात की विदा कराई गई।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक मोहम्मदपुर खाला थाना के एक गांव अपनी बेटी का विवाह सीतापुर जनपद के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के गोड़ा देवरिया गांव से एक लड़के से तय हुई थी। एक जून की देर शाम को बारात थाना क्षेत्र एक गांव पहुंची। द्वारपूजा के बाद शादी की रस्में शुरू हुई।इस बीच में तय दहेज को लेकर वर और कन्या पक्षों में दहेज को लेकर विवाद होने लगा। वर पक्ष वाले जहां ढाई लाख रुपये की मांग कर रहे थे, तो कन्या पक्ष वाले डेढ़ लाख रुपये दे रहे थे।

दोनों के बीच में हाथपाई की नौबत आ गई। तभी किसी ने इसकी सूचना मोहम्मदपुर खाला पुलिस को दी। सूचना पर पहुंचे, सूरतगंज चौकी प्रभारी उमेश वर्मा ने दोनों पक्ष को समझा-बुझा करके मामला रफा-दफा कराया। उसके बाद शादी की रस्में पूरी हुई। उधर पुलिस के मौजूदगी में सोमवार के सुबह विदाई कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

घर के बाहर चारपाई पर सो रहे युवक की 6 टुकड़ों में मिली लाश

» चाचा और पड़ोसी पर हत्या का आरोप, 2 हिरासत में

स्वराज इंडिया संवाददाता

अयोध्या। अयोध्या के बीकापुर कोतवाली से महज 250 मीटर दूर गांव में सोमवार रात एक 22 साल के युवक की दर्दनाक हत्या कर दी गई। सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा युवक घर के बाहर चारपाई पर सो रहा था। सुबह उसका शव छह टुकड़ों में मिला। हाथ-पैर, गर्दन और धड़ अलग-अलग पड़े थे। यह खौफनाक मंजर सबसे पहले उसके पिता ने देखा। चारपाई के नीचे बहता खून देख उनके होश उड़ गए।

चीख-पुकार सुनकर घर वाले दौड़े, गांव में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मृतक के बड़े भाई ने अपने सगे चाचा और पड़ोसी पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि दो आरोपी फरार हैं।

'बेटा बोला था—पापा, बहुत गर्मी है, जनरेटर मंगवा दो'

पिता राजकुमार वर्मा ने बताया, आंधी-बारिश में बिजली चली गई थी। बेटा बार-बार गर्मी की शिकायत कर रहा था। मैंने जनरेटर मंगवाया, सबने खाना खाया और सो गए। रात करीब 2:30 बजे मैं जनरेटर में पानी डालने उठा तो देखा, चारपाई के नीचे खून बह रहा था। पास जाकर देखा तो बेटा टुकड़ों में पड़ा था। चीख निकल गई।

दिनेश वर्मा, मृतक

जमीन की रंजिश में की गई हत्या?

एसपी देहात बलवंत सिंह के मुताबिक, शव पर धारदार हथियार के गहरे निशान हैं। मृतक के भाई विनोद वर्मा ने तहरीर दी है कि जमीन के पुराने विवाद को लेकर उनके सगे चाचा अशोक वर्मा और पड़ोसी रामकृष्ण वर्मा ने हत्या की साजिश रची। आरोप है कि चाचा की पत्नी और एक अन्य पड़ोसी ने भी पूरी योजना में मदद की।पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि दो की तलाश जारी है। मामले की जांच जारी है और जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है।

अयोध्या बिजली विभाग में दौड़ रहा भ्रष्टाचार का करंट

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी अब एक बार फिर चर्चा में है इस बार किसी तीर्थ यात्रा, मंदिर या त्योहार को लेकर नहीं, बल्कि अपने बिजली विभाग में हुए भ्रष्ट और मनमाने तबादलों को लेकर। स्वराज इंडिया को मिली एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में अयोध्या के बिजली वितरण खंड के अंदरूनी हालात ने विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

» मुख्य अभियंता और उनके चहेतों की मनमानी से त्रस्त कर्मचारी

» मुख्य अभियंता की 'चहेती मंडली' और तबादलों का खेल

» मृतकों तक के हुए तबादले, नीतियों की खुली उड़ान

मुख्य अभियंता (वितरण) पर आरोप है कि उन्होंने विभागीय तबादला नीति को ताक पर रखकर अपने चहेतों के हित में तबादले किए। न केवल वरिष्ठता, सेवा काल और पारिवारिक परिस्थितियों को नजरअंदाज किया गया, बल्कि कर्मचारी संघटनों के पदाधिकारियों तक को सजा स्वरूप हटा दिया गया, ताकि कोई आवाज़ बुलंद न कर सके।

महिला और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक को नहीं बख्शा गया

इस बार के तबादले में सबसे अधिक चोट उन कर्मचारियों को लगी है जो या तो महिला हैं या फिर चतुर्थ श्रेणी से ताल्लुक रखते हैं। विभागीय नियमों के अनुसार इन तबकों को विशेष संरक्षण प्राप्त होता है, लेकिन लिस्ट देखकर लगता है कि मुख्य अभियंता ने इन संवेदनशील पहलुओं को नज़रअंदाज़ किया।

तबादला सूची में क्रम संख्या 37 पर दर्ज एक मामला तो भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघता दिखा। कर्मचारी आईडी 17600679, जिसका नाम अंसार अली, जन्मतिथि 20 जून 1986 — को तबादले की सूची में दर्शाया गया है कि उसका जन्म 30 जून 1946 है, और टांडा से बाराबंकी तबादला कर दिया गया है।सूत्रों का दावा है कि अंसार अली वर्षों पहले ही दिवंगत हो चुके हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि मृतक का तबादला क्यों और किस लिए किया गया?

वसूली के लिए खुलेआम लीक किए नाम और मोबाइल नंबर

इस कथित भ्रष्टाचार का सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि तबादले की लिस्ट में कई कर्मचारियों के मोबाइल नंबर और नाम सार्वजनिक कर दिए गए, ताकि उनसे संपर्क कर समझौते किए जा सकें। विभागीय सूत्रों का कहना है कि मुख्य अभियंता कार्यालय के कुछ चाटुकारों ने पैसे की वसूली के लिए यह खेल रचा।तबादलों से आक्रोशित कर्मचारी संघों ने इसे नीति विरुद्ध, नियम विरुद्ध और नैतिकता विरुद्ध बताया है। एक प्रमुख कर्मचारी नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा हमारे संगठन के पदाधिकारियों को भी जानबूझकर दूर-दराज भेजा गया, ताकि कोई विभागीय विरोध खड़ा न हो सके। यह लोकतंत्र नहीं, नौकरशाही का माफिया राज है।

अब स्वराज इंडिया का सवाल यह है कि

-क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इस तबादला घोटाले पर कोई कार्यवाही करेगी?

-क्या मुख्य अभियंता और उनके चहेतों की जांच होगी?

-और सबसे जरूरी, क्या अंसार अली जैसे मृतक कर्मचारियों के तबादले का कोई उत्तरदायी मिलेगा?

स्वराज इंडिया की टीम इस मामले पर निगरानी बनाए हुए है। आने वाले दिनों में हम इन तबादलों से जुड़े और दस्तावेजों, कॉल रिकॉर्ड्स और गवाहों के बयान लेकर एक विस्तृत फॉलोअप रिपोर्ट पेश करेंगे। क्योंकि सवाल उठाना ज़रूरी है अबकी बार तबादला नहीं, जवाब दो सरकार!

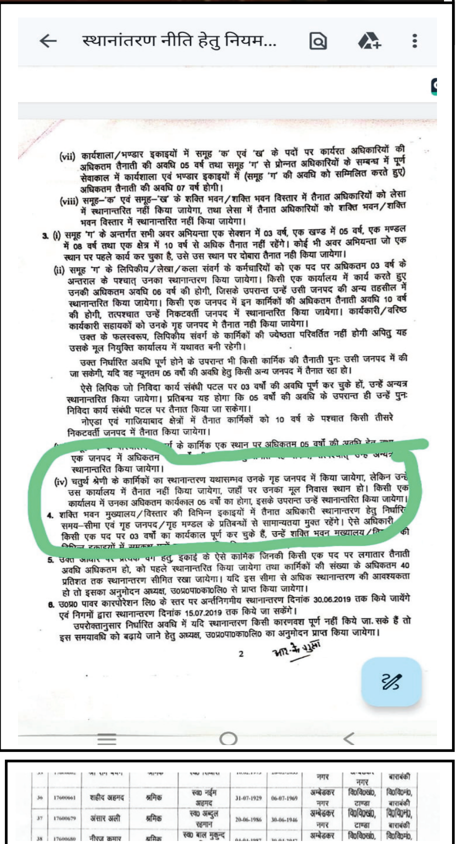

अजब गजब....1986 में पैदा हुए 1946 में रिटायर

नहाने गईं छह लड़कियां डूबी, 4 की मौत

दो को बचा लिया गया, मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को अस्पताल भेजा

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

आगरा। यूपी के आगरा में दर्दनाक घटना हुई। यमुना में नहाने गईं छह लड़कियां डूब गईं। इनमें चार की मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया।

घटना मंगलवार सुबह 10:30 बजे की है। 18 वर्षीय मुस्कान अपनी छोटी बहन संध्या, दिव्या, चचेरी बहन नैना, मौसी की बहन सोनम, सुहानी ओर चचेरे भाई दीपेश के साथ यमुना में नहाने आई थी। सभी बहन-भाई नदी में नहा रहे थे। अचानक संध्या गहरे पानी में चली गई। उसे बचाने मुस्कान और दिव्या गईं। वह भी गहरी पानी में चली गईं।

आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र में नगला नाथू के पास मंगलवार की सुबह यमुना में नहाने पहुंचीं छह लड़कियां नदी में डूब गई। इनमें से चार की मौत हो गई। जानकारी होने पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बचाव कार्य शुरू कर दिया गया।

आधे घंटे की मशक्कत के बाद सभी को गहरे पानी से बाहर निकाला।

युवती सहित 4 की मौत हो गई। दो को बचा लिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को अस्पताल भेजा। गांव का रास्ता ठीक न होने के कारण एंबुलेंस घटनास्थल तक नहीं पहुंच सकी। जिस कारण गांव

के ही लोगों को अपने निजी वाहन बाइक से बच्चियों को अस्पताल ले जाना पड़ा।

अपर पुलिस आयुक्त राम बदन सिंह ने बताया 6 बच्चियां डूबी थीं, 2 को निकाल लिया गया है।

जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कच्चा रास्ता होने के कारण राहत और बचाव कार्य में मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

हरिद्वार नगर निगम जमीन घोटाला में बड़ी कार्रवाई

» उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर दो आईएएस, एक पीसीएस सहित कुल दस अधिकारी निलंबित, दो का सेवा विस्तार समाप्त

भ्रष्टाचार पर धामी सरकार का कड़ा प्रहार

डीएम, पूर्व नगर आयुक्त, एसडीएम पर गिरी गाज

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

हरिद्वार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर निगम हरिद्वार में हुए जमीन घोटाले पर सख्त रुख अपनाते हुए, दो आईएएस, एक पीसीएस अधिकारी सहित सात अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं, इस मामले में तीन अधिकारी पूर्व में निलंबित हो चुके हैं, जबकि दो की पूर्व में सेवा समाप्त की जा चुकी है। इस तरह इस प्रकरण में अब तक 10 अधिकारी निलंबित किए जा चुके हैं।

हरिद्वार नगर निगम द्वारा ग्राम सराय में कूड़े के ढेर के पास स्थित अनुपयुक्त 2.3070 हैक्टेयर भूमि को करोड़ों रुपये में खरीदने पर सवाल उठने के बाद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रकरण की जांच के आदेश दिए थे। जिसके बाद सचिव रणवीर सिंह चौहान ने मामले की प्रारंभिक जांच कर, रिपोर्ट 29 मई को ही शासन को सौंपी थी। इसी जांच रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री ने कार्मिक विभाग को दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जिस पर कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने मंगलवार को सभी सात आरोपित अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद, कार्मिक विभाग ने मंगलवार को हरिद्वार नगर निगम के तत्कालीन प्रशासक और मौजूदा डीएम कर्मेंद्र सिंह, तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी, हरिद्वार के तत्कालीन एसडीएम अजयवीर सिंह, वरिष्ठ वित्त अधिकारी निकिता बिष्ट, वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक विक्की, रजिस्ट्रार कानूनगो राजेश कुमार, हरिद्वार तहसील के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कमलदास को निलंबित कर दिया है।

अब तक हुई कार्रवाई के बारे में

कर्मेन्द्र सिंह - जिलाधिकारी और तत्कालीन प्रशासक नगर निगम हरिद्वार (निलंबित)
वरुण चौधरी - तत्कालीन नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार (निलंबित)
अजयवीर सिंह- तत्कालीन, उपजिलाधिकारी हरिद्वार (निलंबित)
निकिता बिष्ट - वरिष्ठ वित्त अधिकारी, नगर निगम हरिद्वार (निलंबित)
विक्की - वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (निलंबित)
राजेश कुमार - रजिस्ट्रार कानूनगो, तहसील हरिद्वार (निलंबित)
कमलदास -मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, तहसील हरिद्वार (निलंबित)

पूर्व में हो चुकी कार्रवाई

रविंद्र कुमार दयाल- प्रभारी सहायक नगर आयुक्त (सेवा समाप्त)
आनंद सिंह मिश्रवाण- प्रभारी अधिशासी अभियंता (निलंबित)
लक्ष्मी कांत भट्ट- कर एवं राजस्व अधीक्षक (निलंबित)
दिनेश चंद्र कांडपाल- अवर अभियंता (निलंबित)
वेदपाल- सम्पत्ति लिपिक (सेवा विस्तार समाप्त)

हमारी सरकार ने पहले ही दिन से स्पष्ट किया है कि लोकसेवा में 卐पद’ नहीं बल्कि ‘कर्तव्य’ और ‘जवाबदेही’ महत्वपूर्ण हैं। चाहे व्यक्ति कितना भी वरिष्ठ हो, अगर वह जनहित और नियमों की अवहेलना करेगा, तो कार्रवाई निश्चित है। हम उत्तराखंड में भ्रष्टाचार मुक्त नई कार्य संस्कृति विकसित करना चाहते हैं। सभी लोक सेवकों को इसके मानकों पर खरा उतरना होगा।

पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद ऑनलाइन लगेगी शिक्षकों की उपस्थिति

» परिषदीय स्कूलों में तैनात शिक्षकों की मनमानी रोकने के लिए होगी व्यवस्था

वरिष्ठ संवाददाता स्वराज इंडिया

लखनऊ। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद खुल रहे स्कूलों में टैबलेट शिक्षकों की उपस्थिति का समय बताएगा। सभी को प्रत्येक दिन सुबह 7.30 बजे सेल्फी लेकर प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसमें लापरवाही करने पर संबंधित शिक्षकों के वेतन से कटौती की जाएगी।

ऑपरेशन कायाकल्प योजना के तहत नगर क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के सहयोग से प्रत्येक स्कूल की ऊंची बाउंड्रीवाल, स्वच्छ पेयजल, छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय, कक्ष-कक्षाओं के टायल्स आदि लगवाए गए हैं। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा का स्तर बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है। प्रत्येक छात्र को भाषा और गणित विषय में निपुण बनाया जा रहा है। पढ़ाई में कमजोर छात्रों की लगातार निगरानी भी की जा रही है। जिला एवं तहसील स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी समय समय पर स्कूलों का निरीक्षण कर लापरवाही करने वाले शिक्षकों पर कार्यवाही भी करती रही है। इसके बाद भी शिक्षकों पर लेटलतीफी हावी रहती है, तो कुछ शिक्षक पंजिका पर उपस्थिति लगाकर गायब हो जाते हैं। एक अप्रैल से शुरू हुए नए शैक्षिक सत्र में शिक्षकों की इस मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए शासन ने ऑनलाइन उपस्थिति लगवाने का निर्णय लिया है। इसके लिए शिक्षकों को टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं। कंपोजित ग्रांट से सिम खरीदने और इसी ग्रांट से रीचार्ज कराने के निर्देश पूर्व में ही दिए जा चुके हैं। अब ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद खुल रहे स्कूलों में शिक्षकों को टैबलेट से बच्चों के साथ सेल्फी लेकर प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। बीएसए अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि सभी शिक्षकों को इन निर्देशों का पालन हर हाल में करना होगा। अन्यथा की स्थिति में संबंधितों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

ऑनलाइन हुए 12 प्रकार के रजिस्टर-

परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति रजिस्टर के साथ मिड-डे-मील पंजिका, प्रवेश रजिस्टर, कक्षावार छात्र उपस्थिति रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, आय-व्यय एवं चेक इशू पंजिका, बैठक पंजिका, निरीक्षण, पत्र व्यवहार, बाल गणना, पुस्तकालय, खेलकूद पंजिका पर ऑफ लाइन कार्य होता था। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अब शासन ने इन्हें भी डिजिटल कर दिया है।